



## भारत— अमेरिकी सम्बन्धों में ईरान एक मुद्दे के रूप में



इन्दु

शोधछात्रा , राजनीति विज्ञान विभाग ,  
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय  
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ.

### सारांश

अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका इस मुद्दे पर भारत से 2 प्लस 2 वार्ता में बात भी कर चुका है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने पुराने मित्र ईरान से कच्चा तेल आयात करना बंद कर दें क्योंकि प्रतिबंध 5 नवंबर 2018 से लागू हो गया है। परंतु भारत ने ईरान से कच्चा तेल लेना फिलहाल बंद नहीं किया इस संबंध में अमेरिका ने 6 माह का समय दिया उसके बाद भारत के साथ-साथ अन्य देशों को भी ईरान से कच्चा तेल का आयात बंद करना होगा। भारत के नजदीकी अमेरिका से बढ़ने से परिणाम भारत से ईरान दूर होने लगा और तेल आयात करने में ईरान छठे नंबर पर आ गया है। यह दूरी कोई आपसी मतभेद नहीं है बल्कि भारत ईरान की मित्रता के बीच तीसरा देश अमेरिकी दखल अंदाजी है। अमेरिकी प्रतिबंध से ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा लेकिन भारत की ऊर्जा जरूरतों पर इसका प्रभाव कितना पड़ेगा यह विचार करने योग्य सवाल है, क्योंकि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है और यह जरूरत ईरान अभी तक पूरी करता रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान परमाणु समझौते से अलग होना निश्चित रूप से भारत के हित में नहीं है इसमें केवल अमेरिका का ही नजर आ रहा है।

**मुख्य शब्द:** अमेरिका, भारत, ईरान, संबंध, प्रतिबंध, परमाणु-परीक्षण।

### प्रस्तावना:

भारत—अमेरिका के सम्बन्धों की शुरुआत आज से लगभग 70 साल पहले हुई थी। अमेरिका की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू थे। 1949 में नेहरू अमेरिका गये और हैरी ट्रूमैन से मुलाकात की। इसके बाद 1956, 1960, 1961 में यात्राएँ की। 1959 में अमेरिका के राष्ट्रपति ड्रवाइट डी आइजहावर भारत का दौरा करने वाले अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे।

भारत के राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद, प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू से आइजनहावर ने मुलाकात की और भारतीय संसद को सम्बोधित भी किया। 1960 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पुनः नेहरू और आइजनहावर से मुलाकात हुई। विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बंट गया जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ (यू०एस०एस०आर०) और यू०एन० (यूनाइटेड नेशन) थे। शीत युद्ध के दौरान भारत ने इन दोनों महाशक्तियों में जाने के बजाए अपने आपको तटस्थ घोषित कर दिया और 1961 गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के नेता के रूप में विकासशील देशों के लिए

एक नया मंच दिया। परन्तु शीतयुद्ध के दौरान भी एक तरफ रूस से निकटता बढ़ती रही वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से रिश्तों में अनिश्चितता बनी रहती थी।<sup>1</sup>

1962 में भारत-चीन के बीच युद्ध छिड़ गया उस समय भारत के पास रक्षा सामग्री चीन के अपेक्षा बहुत कम थी। युद्ध की स्थिति को देखते हुए प्रधान मन्त्री नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कॅनेडी को खत लिखकर मैकमोहन रेखा को 'सीमा रेखा' मानने का अनुरोध किया था। भारत-पाकिस्तान युद्ध (1965) तक भारत-अमेरिका सम्बन्ध करीबी थे।

सर्वपल्ली राधा कृष्णन अमेरिकी यात्रा (जून 1963) करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1963 में ही अमेरिका के कृषि विशेषज्ञ नॉरमन बोरलॉग भारत की यात्रा पर और भारतीय वैज्ञानिक एम0एस0 स्वामीनाथन से मुलाकात किए इसके बाद ही भारत में 'हरित क्रान्ति' का बीज पड़ा जिससे एक दशक के अन्दर ही भारत खाद्यान्न संकट से उबरते हुए आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद 1966, 1971 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने अमेरिका की यात्रा की। 1971 में भारत-पाकिस्तान का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ था जिसका नतीजा था कि अमेरिका चीन के साथ निकटता दिखाते हुए मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए पाकिस्तान का ही सहयोग किया।

शीत युद्ध काल में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए 'दोस्ती और सहयोग' सन्धि पर हस्ताक्षर किये यह सन्धि गुटनिरपेक्षता की नीति से एकदम उलट कदम था।<sup>2</sup> सर्व विदित है कि अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे जब तक कि सोवियत संघ का विघटन (1991) में नहीं हो गया। वर्तमान में भारत-अमेरिका न केवल राजनीतिक बल्कि रक्षा क्षेत्र के साथ-साथ सामरिक आयुध का बाजार आदि प्रमुख संबंध आगे बढ़ रहा है

### 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध और अमेरिका:

एक तरफ जहाँ भारतीय प्रधान मन्त्री इन्दिरा गाँधी 1971 में बांग्लादेश के शरणार्थी की समस्याओं एवं पाकिस्तानी सैनिकों की क्रूरता को दुनिया एवं अमेरिका को बता रही थी वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन जो एक औरत के शासन के बजाए अपने चहेते फौजी जनरल याह्या खान का पक्ष लेते रहे वही दूसरी तरफ सोवियत संघ ने भारत को मदद का भरोसा दिया। वैसे स्पष्ट बात ये थी कि अमेरिकी प्रशासन भारत एवं पाकिस्तान दोनों के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखता था। उस पर भी इन्दिरा गाँधी को लेकर नापसंदगी हद से ज्यादा थी, और यह बात जगजाहिर हो गई, जब नवम्बर 1971 में पूर्व पाकि० की समस्या को लेकर इन्दिरा गाँधी अमेरिका गई पूर्वी पाकिस्तान की समस्या को लेकर तो राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने हेनरी किसिंजर से इन्दिरा गाँधी के लिए अपमान जनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मुलाकात में ही निक्सन ने चेतावनी दी, कि "अगर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्यवाही की हिम्मत की तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे।"<sup>3</sup>

किसी और देश के लिए अमेरिका की ऐसी चेतावनी डरा देती परन्तु इन्दिरा गाँधी इस धमकी से जरा भी नहीं घबराई और आखिरकार पाकिस्तान ने पहले हमला कर किया जिसका भारत में मुँहतोड़ जवाब दिया। इसी बीच निक्सन ने पाकिस्तान की मदद करने या भारत के खिलाफ कार्यवाही के लिए चीन से सम्पर्क किया क्योंकि निक्सन किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते थे कि भारत-पाकिस्तान पर कार्यवाही करें, परन्तु चीन ने निक्सन के मन्सूबों पर पानी फेर दिया क्योंकि चीन की यह मानता था कि पूर्वी पाकिस्तान की स्वतन्त्रता ही एक मात्र विकल्प है। तब इन्दिरा गाँधी पर संघर्ष-विराम के लिए दबाव डाला गया परन्तु इन्दिरा गाँधी ने मना कर दिया इससे निक्सन बौखला गए और अपने सातवें बेड़े को हिन्द महासागर में भेजा परन्तु उनके सामने सोवियत संघ आकर खड़ा हो गया भारत ने संघर्ष-विराम किया परन्तु भारतीय फौज के ढाका में 17 दिसम्बर 1971 के पलैग मार्च के बाद सर्वविदित है कि अमेरिका के सातवें बेड़े के पहुँचने से पहले ही पाकिस्तान ने 90 हजार सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और निक्सन देखते ही रह गये। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन इसलिए भी भारत से खफा थे क्योंकि उस समय अमेरिका 'या तो आप हमारे साथ हैं या फिर खिलाफ

<sup>1</sup> भारत-अमेरिका सम्बन्ध : इतिहास के आइने में-BBC News हिन्दी, पृ0सं0 2

<sup>2</sup> वही, पृ0 सं0 4

<sup>3</sup> News 18 Hindi November 19, 2018, 12 :35 PM IST

है' की नीति पर चल रहा था यही वजह थी कि निक्सन और किसिंजर इन्दिरा गाँधी और भारतीयों के बारे में अपशब्द बोल रहे थे जिसे भारतीय जनमानस में उनके खिलाफ रोष व्याप्त हो गया था और 1971 के युद्ध में भारत और अमेरिका के सम्बन्ध बहुत निम्न स्तर पर आ गये थे। राष्ट्रपति निक्सन तो इन्दिरा गाँधी को बिल्कुल भी पसन्द नहीं करते थे। 1971 के बाद जहाँ इन्दिरा गाँधी पूरे विश्व में एक सशक्त महिला बनकर उभरी वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा देना पड़ा।

### शीत युद्ध के दौरान भारत—ईरान संबंध और अमेरिका

स्वतंत्रता के बाद भारत में गुटनिरपेक्ष रहने की घोषणा की, इससे भारत के साथ अमेरिका के संबंधों में तनाव आने लगा। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बँट गया था और अमेरिका का यह कहना था कि जो उनके साथ नहीं है वह देश हमारे विरुद्ध है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर सैन्य सामग्री हासिल किया जबकि अमेरिका यह बखूबी जानता था कि पाकिस्तान सैन्य सामग्री का इस्तेमाल किसी साम्यवादी के विरुद्ध नहीं वरन् भारत के खिलाफ ही कर सकता है। इस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करके दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर दिया था। जिससे भारत—अमेरिका संबंधों में कटुता और बढ़ गई।

अमेरिका को यह लगता था कि भारत तकनीकी और आर्थिक सहायता पाने के लिए गुटनिरपेक्ष नीति को छोड़ देगा अमेरिकी खेमे में शामिल हो जाएगा परंतु ऐसा नहीं हुआ।

1950 के दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति कैंनेडी ने सत्ता संभाला तब लोगों को लगा कि भारत के साथ अमेरिका के संबंधों में सुधार आएगा क्योंकि कैंनेडी, नेहरू से प्रभावित थे। उन्होंने शीत युद्ध का तनाव घटाने का लगभग प्रयास किया। 'पीस कोर' नामक अमेरिकी शांति सेना की स्थापना की। इसके स्वयंसेवकों, ने भारत में आकर अमेरिका के पक्ष में भारतीय जनता के हृदय में स्थान पाने में बहुत योगदान किया।

### 18 मई 1974 परमाणु परीक्षण और अमेरिकी प्रतिबंध

1971 से ही भारत—अमेरिकी सम्बन्ध रसातल में थे। 18 मई 1974 को भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने के पश्चात सम्बन्ध और निम्न स्तर पर चले गये। इस परीक्षण के विरोध में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने प्रतिबन्ध लगा दिये। अमेरिका—पाकिस्तान की वजह से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में लगा रहता था। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत गुटनिरपेक्षता की नीति की पाता करने वाला देश था और अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी हर बात का समर्थन करें परन्तु भारत ऐसा नहीं कर रहा था। भारत को शक्ति सन्तुलन के लिए परमाणु परीक्षण में बहुत कठिनाई भी आई लेकिन अन्ततः परमाणु परीक्षण करने में भारत सफल हुआ। अमेरिका ने भारत पर अनेक प्रतिबन्ध लगाए परन्तु भारत की आर्थिक स्थिति पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और अमेरिका ने पांच वर्षों के अन्दर में प्रतिबन्ध हटा लिए<sup>4</sup>

### 1998 में भारत का परमाणु परीक्षण और अमेरिकी प्रतिबंध

11, 13 मई 1998 को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध (बुद्ध मुस्कुराए) नाम से सफल परमाणु परीक्षण किया गया था यह परीक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। इसे बड़ी ही गोपनीयता के साथ पूरा करना भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक कठिन चुनौती थी उस समय अमेरिका खुफिया एजेंसी सी.आई.ए. भारत पर कड़ी नजर रख रहा था परंतु भारत अमेरिका सेटैलाइट्स को चकमा देकर परमाणु विस्फोट किया इससे अमेरिका नाराज हो गया क्योंकि भारत परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। हालांकि भारत ने हमेशा कहा है कि वह परमाणु बम का परीक्षण शांति के लिए किया है परंतु बौखलाए अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए लेकिन बाद में यह प्रतिबंध हटा लिया गया था भारत का यह परमाणु परीक्षण दुनिया के लिए उभरती हुई एक परमाणु संपन्न राष्ट्र का उदय था।<sup>5</sup>

<sup>4</sup> वही, पृ० सं० 5

<sup>5</sup> नवभारत टाइम्स. इंडिया | www.navbharattimes.com visited on 11 May 2018

### भारत-अमेरिकी संबंध – एक घटनाक्रम

1947 के बाद से शीतयुद्ध की समाप्ति तक भारत-अमेरिका के संबंध उसी धरातल पर थे, जिस धरातल पर भारत-पाकिस्तान, चीन-USSR के संबंध थे। भारत-सोवियत संघ के संबंधों को अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से शीत युद्ध की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ही देखा था। 1991 से सोवियत संघ के पतन के पश्चात अमेरिका का भारत के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित अवश्य हुआ, परंतु शीत युद्धात्तर काल में भारत के द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद ना करने के कारण भारत-अमेरिका संबंधों में विवाद का एक प्रमुख कारण बना रहा। 1998 में अत्यधिक तनावपूर्ण स्थिति तब उत्पन्न हुई अमेरिका ने भारत के परमाणु परीक्षण के पश्चात करे आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए थे।

### वर्तमान में भारत-अमेरिका संबंध

21वीं सदी में भारत अमेरिका के बीच नई राजनीतिक साझेदारी में बढ़ोतरी होने लगी है और दक्षिण एशिया में अमेरिकी हितों के विस्तार के फलस्वरूप भारत उसके लिए अति महत्वपूर्ण बन गया है। 9/11 के बाद दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध, वैश्विक आर्थिक मंदी और एशिया में उभरते नए शक्ति केंद्रों के परिदृश्य में अपने संबंधों में आमूलचूल सुधार किये। 2006 में भारत-अमेरिका के मध्य असैन्य परमाणु (123) समझौते के पश्चात अमेरिका ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में मान्यता प्रदान की।

भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय थी। एशिया में चीन को संतुलित करने के लिए भी अमेरिका, भारत को एक महत्वपूर्ण धुरी मानता है। हाल के वर्षों में भारत-अमेरिकी संबंधों में प्रगाढ़ता आई है, दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और पारस्परिक हितों पर नियमित संवाद स्थापित कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-अमेरिका के लिए जुड़वा देश की संज्ञा दी थी और आपसी संदेहों को दूर करने की बात कही, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में कहा है कि दोनों देश के मध्य द्विपक्षीय संबंध 21वीं सदी की निर्णायक साझेदारी है।<sup>6</sup>

भारत-अमेरिका संबंध वर्तमान में यात्रा करते सहयात्री की तरह हो गए हैं जो अपने-अपने हितों को पूरा करने के लिए एक ही वाहन में यात्रा कर रहे हैं और यह रिश्तों का वाहन पथरीले रास्ते से होकर गुजर रहे हैं, जिसमें आंतरिक विरोध और नकारात्मक तत्व बांधा उत्पन्न कर रहे हैं। यहीं नकारात्मकता आपसी संबंधों में क्षति पहुंचा रही है परंतु यह नकारात्मकता कम करने में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग ने दोनों देशों के आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं।

***“भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी का महत्व यह है कि वो एक ऐसे जहाज में सवार हैं जो कायापलट की यात्रा पर है।”<sup>7</sup>***

भारत और अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग से आर्थिक और रक्षा में कुछ वर्षों से बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है अमेरिकी गृह मंत्री जॉन केरी और वाणिज्य मंत्री पेन्नी प्रिट्जर नए संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए 22 सितंबर 2015 को भारत अमेरिका कूटनीतिक, रक्षा और राजनयिक संबंधों पर मुहर लगाई।<sup>8</sup>

‘भारत-अमेरिका संबंध के बारे में भारत में अमेरिकी राजदूत के केनेथ आई. ने अपने भाषण में कहा कि “भारतीय-अमेरिकी विविधता, गतिशीलता, बहुलतापूर्ण लोकतंत्र के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उधम, मुक्त बाजार, मानवाधिकार के मूलभूत मूल्यों को साझा करते हैं। व्यापार, वाणिज्य की स्वतंत्रता तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार विवादों का हल शांतिपूर्ण ढंग से करने में हमारे हित समान हैं यही हमारी मित्रता का आधार है।”<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ( भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ आई जस्टर का भाषण) <http://inusembassy.gov/> visited in 11 january 2018.

<sup>9</sup> Ibid.

### भारत और अमेरिका के बीच 123 असैन्य परमाणु सहयोग समझौता और ईरान

भारत—अमेरिका के बीच 123 असैन्य परमाणु सहयोग समझौता पर जुलाई 2005 में हस्ताक्षर हुए इस समझौते से भारत—अमेरिकी संबंधों की एक नई सामरिक संबंधों की शुरुआत हो गई। सर्वविदित है कि हेनरी हाइड एक्ट 1950 अमेरिका को उन्हीं देशों के साथ परमाणु क्षेत्र में सहयोग (व्यापार) की इजाजत देता है जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया हो परंतु भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर किए बिना ही यह समझौता किया। इस समझौते ने कहीं ना कहीं भारत—ईरान संबंधों में कटुता घोलने का कार्य किया है क्योंकि भारत—अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग हासिल कर रहा था और दूसरी तरफ ईरान को हासिल न हो इसका अमेरिका के साथ मिलकर विरोध भी कर रहा था।

123 समझौता कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि अमेरिका यह नहीं चाहता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे। 2012 तक भारत—ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को सही ठहराता रहा, यह अमेरिकी प्रभाव का स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा था परंतु कुछ समय पश्चात भारत ने इस दबाव से उबरते हुए चाबाहार बंदरगाह का निर्माण कर दिया यह परियोजना 2012 में शुरू हुई थी जो आज लगभग मूर्त रूप ले चुकी है। इस प्रकार देखे तो भारत—अमेरिका संबंधों में समय—समय पर उतार—चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं।

### शीत युद्ध के बाद भारत—ईरान संबंध और अमेरिका की भूमिका

ईरान—भारत का संबंध, भारत—अमेरिकी संबंधों में एक अड़चन बनकर रह गया है। कई भारतीय विद्वानों ने आरोप लगाया है कि अमेरिका, भारत की ईरान नीति को प्रभावित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ईरान के खिलाफ भारत का वोट और दिसंबर 2010 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, जिसने एशियाई समाशोधन संघ के माध्यम से ईरान को तेल भुगतान करने से रोक दिया। इन मामलों में से प्रत्येक में भारत पर जबरदस्त अमेरिकी दबाव था और भारत की नीति पर प्रभाव पड़ सकता था।

भारत इस समय अपनी विदेश नीति के विकल्पों को किस तरह पुनर्गठित करता है, यह दीर्घकालिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गतिशीलता को एक निर्णायक मोड़ पर ले जायेगा, विशेष रूप से पश्चिम/एशिया के लिए स्ट्रोतजिक एवं भू-राजनीतिक पारी के संदर्भ में महत्वपूर्ण होगा। भारत धीरे-धीरे विश्व मामलों में अपने बढ़ते प्रभाव के साथ उभर रहा है और यह प्रभाव शक्ति संतुलन में बदलाव के नए अवसरों के साथ—साथ भारत के लिए चुनौतियां भी खोली हैं।<sup>10</sup>

भारतीय विदेश नीति आज अपने सर्वश्रेष्ठ समय में है जिसमें शीत युद्ध के बाद से एक बदलाव स्पष्ट देखा गया है। शीत युद्ध के दौरान इसकी विदेश नीति जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा से चलती थी, यह नीति गुटनिरपेक्षता पर आधारित थी, बाद में अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए सोवियत संघ के साथ खड़ी दिखाई दी थी। इसकी गुटनिरपेक्ष नीति, विदेश नीति के निर्णय लेने की क्षमता पर अधिक प्रभावी दी थी। दो महाशक्तियों द्वारा लगाए गए अवरोधों के बाहर, तटस्थता की तुलना में शीत युद्ध का अंत सुरक्षा से वंचित भारत यूएसएसआर प्रदान किए गए सहायता और आर्थिक संकट ने भारतीय नीति निर्माताओं को आर्थिक और विदेशी नीतियों में अधिक व्यावहारिक बनने के लिए मजबूर किया।<sup>11</sup>

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका के साथ भारत के संबंध ने एक नई व्यावहारिक दृष्टि की अभिव्यक्ति हैं। अमेरिका के साथ भारत की सामरिक निकटता ने ईरान के प्रति भारत की नीति पर पश्चिम का ध्यान केंद्रित किया है। भारत चाहता है कि ईरान के साथ अपने संबंधों को आदर्श रूप से द्विपक्षीय संबंधों के दायरे में बने रहने के लिए किसी तीसरे देश के साथ उसके संबंधों पर कोई असर न पड़े। परंतु ऐसा अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंधों के ऐसा नहीं हो पाया। भारत—ईरान संबंध, 2005 में भारत—अमेरिका संबंधों के लिए एक कारक बन गया, जब भारत—अमेरिका परमाणु समझौते पर बातचीत की जा रही थी।

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid.

## भारत-अमेरिका संबंध में ईरान एक मुद्दे के रूप में

### भारत-अमेरिका संबंध

दोनों देश अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के शिकार हैं इसलिए आतंकवाद से मुकाबला करने में सहयोग करते हैं। सामान्य हित का एक अन्य क्षेत्र हिंद महासागर है, जहां व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित करने में अमेरिका और भारत दोनों की समान दिलचस्पी है। भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने वाला अप्रभावी कारक दक्षिण एशिया में चीन का उदय है। भारत और अमेरिका दोनों को इस बात की चिंता है कि चीन कैसे व्यवहार करेगा, क्योंकि यह एक वैश्विक शक्ति में बदलता जा रहा है। हालाँकि दोनों देशों ने चीन से सन्धि की है, और इसके साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध हैं।

भारत के पड़ोस में, दोनों अफगानिस्तान में स्थिरता लाने में रुचि रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि यह फिर से आतंकवादियों के लिए पनाहगाह बने। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया। जबकि ईरान ने भारत का समर्थन नहीं किया है।<sup>12</sup>

अमेरिका में बढ़ते भारतीय अमेरिकी समुदाय के साथ-साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देते हुए सामाजिक संबंधों ने साझेदारी को और आगे बढ़ाया है। यह भारत-अमेरिकी परमाणु समझौता ही था जिसने वास्तव में भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया<sup>13</sup> साथ ही यह समझौता भारत-ईरान के पारस्परिक संबंधों को रसातल में ले जाने का काम भी किया था।

भारत-अमेरिका संबंध भी उनके मतभेदों के बिना नहीं हैं। उदाहरण के लिए, भारत-ईरान संबंध पिछले कुछ समय से एक अथाह गहराई में चलता जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के साथ भारत के करीबी संबंधों को अमेरिका-भारत संबंधों के भविष्य की सबसे बड़ी बाधा के रूप में बताया जो हमारी रणनीतिक साझेदारी को प्रभावित कर सकता है।<sup>14</sup> भारत-ईरान संबंधों ने अमेरिका के भीतर चिंताएं बढ़ाई हैं।<sup>15</sup> भारत-ईरानी संबंध कुछ अमेरिकी नीति-निर्माताओं के लिए अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। इस तरह देखा जाए तो भारत इस समय ईरान और अमेरिका से अपने संबंधों को संतुलन करने में लगा हुआ है।

अमेरिका-ईरान संबंधों में सबसे बड़ी चुनौती ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिका का मानना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बाद से परमाणु हथियारों को विकसित करने के लिए यह एक चाल है। अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार क्षमता हासिल करने की अनुमति नहीं देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। अमेरिका सहयोगी देशों के साथ, ईरान पर अपने परमाणु कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए दबाव डाला और अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा कठोर कार्यवाही की पैरवी किया है। अमेरिका का मानना है कि एक परमाणु ईरान वाशिंगटन के हितों के खिलाफ मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल देगा और इस क्षेत्र को संभावित रूप से अस्थिर कर देगा। वाशिंगटन ने अक्सर ईरान पर रासायनिक और जैविक हथियार हासिल करने का आरोप लगाया है परंतु ईरान ने इन आरोपों का हमेशा से खण्डन किया है।

ईरान ने अमेरिका पर लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं और आंदोलनों का समर्थन करके फारस की खाड़ी के स्वायत्ततावादियों का समर्थन करके देश में परेशानी पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को लागू करने के अलावा ईरान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग करने का आरोप भी लगाया। इस प्रकार, ईरान-अमेरिकी संबंधों की तुलना जाये तो अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ईरान को विश्व राजनीति में अलग-थलग करने का भी है। अमेरिका के पास दूसरे देशों के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश का पुराना इतिहास रहा है। शीत युद्ध के दौरान यह सोवियत संघ और क्यूबा थे, आज ईरान है।

### भारत ईरान संबंधों, में भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता का प्रभाव

भारत और अमेरिका के बीच पहली बार सितंबर 2018 में 2+2 वार्ता हुई। प्रमुखतः इस वार्ता में दोनों देशों में द्विपक्षीय रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने के साथ वैश्विक राजनीति में विशेष सहयोग देने

<sup>12</sup> <http://www.deshbandhu.co.in/cdn.ampproject.org>.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> प्रो. मो. बदरुल आलम, वर्ल्ड फोकस फरवरी 2015, भारत की ऐतिहासिक समीक्षा और मोदीमय अमेरिका

<sup>15</sup> नवभारत टाइम्स. इंडिया। [www.navbharattimes.com](http://www.navbharattimes.com) visited on 13 November 2018

पर बल दिया गया। 2+2 वार्ता में भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस से बातचीत हुई। अमेरिका ने इस वार्ता में भी ईरान से कच्चा तेल के आयात को मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयास किया। ज्ञातव्य है कि ईरान से कच्चा तेल आयात करने में भारत शीर्ष देशों में शामिल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले वर्ष ईरान से लगभग सात अरब डॉलर का तेल आयात किया था। इसी को देखते हुए अमेरिका-भारत पर बहुत दबाव डाल रहा है कि ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद करे।<sup>16</sup>

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि दूसरे देशों से भी वह ईरान से तेल आयात को 5 नवंबर 2018 से अमेरिकी एक पक्षीय प्रतिबंध लग जाएगा, प्रतिबंध के बारे में घोषणा कर दिया है इसलिए ईरान से कच्चे तेल का आयात सभी देश को बंद करना होगा।<sup>17</sup>

प्रतिबंध के बारे में भारत ने कहा है कि इस मामले में बिना दबाव और देशहित में ही फैसला किया जाएगा। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से अमेरिका और ईरान का संबंध फिर से कटुता की तरफ बढ़ गया है। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी ने कहा है कि इस प्रतिबंध से ईरान पर आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा।

2+2 वार्ता के बीच भारत-ईरान चाबहार बन्दरगाह में पेमेंट कैसे हो? इस काम पर लग गए हैं, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत-ईरान को पूरा भुगतान नहीं कर सकता है। प्रतिबन्धित समय में आधा भुगतान होगा, आधा प्रतिबंध हटने के बाद रूपए में भुगतान के लिए ईरान मान गया है, और वित्तीय लेन-देन को पूरा करने के लिए दिल्ली में ईरान से पासरगाड बैंक और यूको बैंक से बातचीत चल रही है, इससे ईरान पर प्रतिबंध से निपटने में मदद मिलेगी।

भारत में तेल के बदले अनाज फार्मूले पर ईरान से बातचीत चल रही है इससे भारत पर पैसे का भुगतान करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगा, और ईरान को जरूरी सामान भी मिल जाएगा जो भारत से निर्यात होता है। अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिलने के बाद भारत प्रतिबंध की अवधि में कच्चे तेल का 40-45 प्रतिशत हिस्से का भुगतान भारतीय रूपए में होगा, शेष भुगतान यूरो में होगा। भारतीय रूपए में जो भुगतान होगा उसका उपयोग ईरान चावल, दवाइयां, कपड़ा अन्य खाद्य सामग्री आयात में कर सकेगा।<sup>18</sup>

सामरिक दृष्टि से ईरान भारत का महत्वपूर्ण सामरिक देश है। वह भारत को तेल आपूर्ति करने वाला तीसरा बड़ा देश है- 2 करोड़ 72 लाख टन तेल गत वर्ष मिला। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के खतरे के सामने मुंबई व गुजरात को 7200 किलोमीटर लम्बे उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ने का मार्ग ईरान के चाबहार, बंदर अब्बास होते हुए अजरबैजान तथा रूस के सेंट पीटर्स बर्ग तक पहुंचता है जो भारत के लिए इतना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है।

सत्य यह है कि भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संवाद के 50 से ज्यादा मंच हैं। आपसी व्यापार 115 अरब डालर का है। भाषा, लोकतंत्र और पुराने संबंधों की साझेदारी के बावजूद अमेरिका कभी रूस की तरह भारत का भरोसेमंद मित्र नहीं रहा। फिर भी वर्तमान भू-राजनीतिक समीकरणों में भारत, अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया का सामरिक चीन के समक्ष एक अविजेय ध्रुव बनाता है। इसलिए ट्रम्प की सनक भरी उतार-चढ़ाव वाली विदेश नीति के बावजूद भारत को एक संवदेनशील शक्ति संतुलन बनाने की जरूरत होगी।

भारत की विदेश नीति भारत को ही तय करनी होगी, अमेरिका को उसका कोई अधिकार नहीं। यह हमारा विषय है कि हम अपने मित्र और सहयोगी तय करें। मोदी की विदेश नीति का सफल पक्ष यह है कि इजरायल, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों के साथ जिनका कोई परस्पर मैत्री संबंध नहीं- बल्कि प्रबल शत्रुताएं हैं- भारत के अच्छे संबंध हैं। जो नीति भारत-हित साधे वही नीति हमारे राजनयिक संबंधों की कसौटी है। अमेरिका, अमेरिकी हितों के लिए काम करें, लेकिन अमेरिकी हितों के लिए भारत कभी अपनी विदेश नीति में बदलाव नहीं लाएगा- यह निश्चित है। यही मोदी नीति है। ट्रम्प और निक्की हेली को भारत के मित्र चुनने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका अपने सामरिक हितों के लिए विश्व के तानाशाहों, शाही परिवारों, अलोकतांत्रिक एवं अत्यंत मध्ययुगीन मानसिकता के शासकों से अच्छे संबंध बनाकर चलता है। लेकिन भारत जैसे महान

<sup>16</sup> <http://printfriendly.com/> visited on 09 May 2018

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> प्रभा साक्षी तरुण विजय 6 जुलाई 2018 | [www.prabhasakshio.com/](http://www.prabhasakshio.com/) visited on December 2018

लोकतांत्रिक देश पर आतंकी हमले करने वाले पाकिस्तान पर ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करता, जो वह ईरान पर करना चाहता है।

यह हमारा अधिकार है कि हम अपने मित्र और सहयोगी स्वयं तय करें। भारत की विदेश नीति का सफल पक्ष यह है कि इजरायल, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों के साथ जिनका कोई परस्पर मैत्री संबंध नहीं है, भारत के उनसे अच्छे संबंध हैं। अमेरिका, अपने हितों के लिए काम करें, लेकिन अमेरिकी हितों के लिए भारत कभी अपनी विदेश नीति में बदलाव नहीं कर सकता है।

### भारत—ईरान संबंधों में अमेरिका की भूमिका का परीक्षण

अमेरिका ने ईरान पन सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका इस मुद्दे पर भारत से 2+2 वार्ता में बात भी कर चुका है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने पुराने मित्र ईरान से कच्चा तेल आयात करना बंद कर दें क्योंकि प्रतिबंध 5 नवंबर 2018 से लागू हो गया है, परंतु भारत ने ईरान से कच्चा तेल लेना फिलहाल बंद नहीं किया है। इस संबंध में अमेरिका ने 6 माह का समय दिया है। 6 माह के अन्दर ही भारत के साथ—साथ अन्य देशों को भी ईरान से कच्चा तेल का आयात बंद करना होगा।<sup>19</sup>

ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स में लिखा है कि "साल 2012 से 2016 के बीच ईरान के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बावजूद ईरान भारत को कच्चा तेल बेचने वाला सबसे बड़ा देश था"<sup>20</sup> परंतु भारत के नजदीकी अमेरिका से बढ़ने पर ईरान—भारत से दूर होने लगा और तेल आयात करने में ईरान छठे नंबर पर आ गया है। यह दूरी कोई आपसी मतभेद नहीं है बल्कि भारत—ईरान की मित्रता के बीच तीसरा देश (अमेरिका) की दखल अंदाजी है। अमेरिकी प्रतिबंध से निःसंदेह ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा, लेकिन भारत की ऊर्जा जरूरतों पर इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, यह विचार करने योग्य सवाल है, क्योंकि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की महती जरूरत है, और यह जरूरत अभी तक ईरान पूरी करता आ रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान परमाणु समझौते से अलग होना निश्चित रूप से भारत के हित में नहीं है। इसमें केवल अमेरिका का ही हित नजर आ रहा है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत—ईरान से तेल आयात बंद करके उससे तेल आयात करे। यह आयात रुपया में नहीं डॉलर में होगा जबकि भारत—ईरान को रुपया, रुबल या यूरो में भुगतान करता है।

भारत ने अमेरिकी प्रतिबंध को अभी ज्यादा महत्व नहीं दिया है, परंतु भारत को दोनों देशों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा, नहीं तो भारत अमेरिकी संबंधों के बीच, भारत एक परममित्र को खो देगा यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होगा।

### निष्कर्ष

भारत ईरान संबंध में अमेरिका की भूमिका के परीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से तो दोनों ही देश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक के पास रक्षा तकनीकी संसाधन है तो दूसरे के पास अप्राकृतिक संसाधन इसलिए भारत—अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश में लगा हुआ है। एक तरफ देखा जाए तो अमेरिका एशिया में उभर रही नई चुनौतियां एवं खतरों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी साबित हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में ऊर्जा सुरक्षा से भारत का भविष्य सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत—ईरान कभी सीमा साझा करते थे, परंतु पाकिस्तान के जन्म के बाद सरहद बंट गई लेकिन वहीं है। समय के साथ संबंधों में उतार—चढ़ाव होता रहा है। अमेरिका को इस द्विपक्षीय रिस्तों का सम्मान करना चाहिए और समझना चाहिए, कि किसी भी इस द्विपक्षीय संबंध की तरह ही ईरान के विभिन्न मुद्दों पर अमेरिका और भारत के बीच भी मतभेद हो सकते हैं, तथापि इन्हें दिल्ली और वाशिंगटन के संबंधों के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए, आदर्श राजनीति भी यही कहती है। भारत को ईरान और अमेरिका दोनों में से कोई एक का चयन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

<sup>19</sup> नवभारत टाइम्स. इंडिया। [www.navbharattimes.com](http://www.navbharattimes.com) visited on 13 November 2018

<sup>20</sup> <http://printfriendly.com/> visited on 15 November 2018



भारत अमेरिका का आधिकारिक सहयोगी नहीं है, इसलिए उसे ईरान पर अपने हित में फैसले लेने का पूरा हक होना चाहिए। परंतु अमेरिका ने जब से ईरान पर प्रतिबंध लगाया है तब से वह भारत पर दबाव डाल रहा है, कि भारत ईरान से कच्चा तेल का निर्यात बंद कर दे। भारत की ऊर्जा जरूरतें ईरान को अमेरिका के लिए बलि नहीं चढ़ा सकती हैं, क्योंकि चीन की ईरान ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ती हो उपस्थिति और ईरान के साथ पाकिस्तान का संबंधों को देखते हुए ईरान को रणनीतिक गणना से बाहर नहीं निकाला जा सकता है अमेरिका रणनीतिक रूप से कोशिश में लगा है कि भारत के संबंधों को अमेरिका से ज्यादा महत्व न मिले। यही वजह है कि अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते करीबी संबंधों ने ईरान के साथ विकसित पारंपरिक संबंधों पर पाबंदी लगा दिया है। अमेरिका द्वारा ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों से ईरान का अमेरिका और भारत दोनों से संबंध रसातल में जा रहे हैं।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रभा साक्षी तरण विजय 6 जुलाई 2018 | [www.prabhasakshio.com/](http://www.prabhasakshio.com/) visited on December 2018
2. ऊमा पुरुषोत्तमन, (2012) रुटलेग, टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप
3. प्रो. मो. बदरुल आलम, वर्ल्ड फोकस फरवरी 2015, भारत की ऐतिहासिक समीक्षा और मोदीमय अमेरिका
4. ईरान के संबंध में भारत पर बढ़ता अमेरिकी दबाव, क्या भारत अमेरिका के आगे झुकेगा? या देशहित में लेगा फैसला? 7 सितंबर 2018
5. अमेरिका ने 2+2 वार्ता के बीच चाबहार पेमेंट मैकेनिज्म पर काम करने में जुटे भारत ईरान 7 सितंबर 2018
6. भारत-अमेरिका सम्बन्ध : इतिहास के आइने में-BBC News हिन्दी, पृ0सं0 2
7. वही, पृ0 सं0 4
8. News 18 Hindi November 19, 2018, 12 :35 PM IST
9. NDTV May 18, 2017, 11:32 IST
10. वर्ल्ड फोकस, जनवरी 2017, डॉ० मनन द्विवेदी "भारत-अमेरिका द्विपक्षीय इतिहास का नया तारा : तेजी से बढ़ते लक्षण-निर्यात, पेज न. 103
11. वही, पेज न. 104
12. वही, पेज न. 107
13. भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ( भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ आई. नेता ई जस्टर का भाषण
14. Harsh V. Pant] ^ India's rrelation with Iran: much ado about nothing; the washing Quaterly, 34(1), P.1
15. [www.jansatta.com](http://www.jansatta.com) visited on September, 24, 2018
16. <http://www.claws.com> visited on September, 24, 2018
17. नवभारत टाइम्स. इंडिया | [www.navbharattimes.com](http://www.navbharattimes.com) visited on 13 November 2018
18. <http://www.bbc.com/cdn.ampproject.org/> visited on 25 December 2018
19. [Sansarloachan.in/](http://Sansarloachan.in/) Iran-nuclear deal- P5 hindi
20. भारत-अमेरिका सम्बन्ध : इतिहास के आइने में-BBC News हिन्दी, पृ0सं0 2

### पत्र-पत्रिका

1. वर्ल्ड फोकस
2. चाणक्य
3. भारत

### समाचार पत्र

1. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया
2. नव भारत टाइम्स
3. द हिन्दू



**इन्दु**

शोधछात्रा , राजनीति विज्ञान विभाग , बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय  
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ.